



**ऑनलाईन प्रक्रिया में आई
सी टी लैब और स्मार्ट क्लास
रूम संचालन में विद्यालय
प्रमुख की भूमिका –
राजस्थान के सन्दर्भ में**

लेखक : श्रीमती शमीम

**राजस्थान स्कूल लीडरशिप अकादमी
सीमेट, जयपुर, राजस्थान**

उद्देश्य :-

1. विद्यार्थियों और शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा और तकनीक के लिए तैयार करना है।
2. ऑनलाइन प्रक्रिया में आई सी टी लैब और स्मार्ट क्लासरूम के उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना।
3. विद्यार्थियों को डिजिटल विश्व और प्रभावी रोजगार के आवश्यक कौशल को प्राप्त करने योग्य बनाना।
4. विद्यार्थियों में नवीनतम शैक्षिक तकनीकों और उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षा में नवाचार लाने का प्रयास करना, जो छात्रों की गतिविधियों और सीखने को बेहतर बनाने में मदद करता है।

प्रस्तावना :-

"शिक्षा में तकनीकी साधनों का उपयोग करने से शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा और दिशा मिलती है, जो हमारे छात्रों को आधुनिक विश्व में सफलता की दिशा में ले जाती है।" - डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

"शिक्षा में तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना शिक्षा को एक नई दिशा में ले जाता है और समृद्धि की अवसरों को निर्मित करता है।" - अल्बर्ट आइंस्टीन

डिजिटल शिक्षा :-

आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल शिक्षा (तकनीकी शिक्षा) डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। डिजिटल माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से ज्ञान और जानकारी आसानी से साझा किया जा सकता है। भारत में भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में डिजिटल शिक्षा का महत्व अत्यधिक बढ़ रहा है। यह एक क्रांतिकारी पहल है जो लाखों लोगों, विशेषकर स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने और अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने में सहायता करेगी। डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी के व्यापक और विशाल भविष्य को देखते हुए भारत सरकार डिजिटल शिक्षा को बहुत तेजी से बढ़ावा दे रही है और पूरे देश में इसकी सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में राज्य सरकार भी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए (ऑनलाइन शिक्षण हेतु कक्षा-कक्ष, विभिन्न ऑनलाइन शैक्षिक पोर्टल्स, वर्चुअल स्कूल, लाइव क्लासेज को प्रारम्भ किया) शिक्षा में अनेक नए आयाम प्रस्तुत कर रही है। इसके लिए विद्यालय प्रमुख को सबसे पहले स्वयं प्रशिक्षित होना होगा उसके बाद अपने विद्यालय के शिक्षक को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा ताकि विद्यार्थी प्रशिक्षित शिक्षक से डिजिटल शिक्षा प्राप्त कर सफलता की बुलंदियों को छू सकें।

डिजिटल शिक्षा के लाभ:-

- विद्यार्थी किसी भी समय, किसी भी स्थान पर आसानी से सीख सकता है।
- डिजिटल शिक्षा का विद्यार्थियों पर समग्र रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे जब चाहें अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।
- विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले सकते हैं और देश के कुशल शिक्षकों से अध्ययन कर सकते हैं।
- शिक्षक, अध्यापन कार्य को और अधिक आकर्षक और रुचिकर बना सकते हैं।

डिजिटल शिक्षा में आने वाली चुनौतियाँ :-

- सभी के लिए इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता नहीं है।
- सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक शिक्षा की पहुंच नहीं होना और समस्त शिक्षकों को तकनीकी उपयोग में प्रशिक्षित करना।

विद्यालय प्रमुख विद्यालय प्रबंधन समिति और शिक्षकों की सहायता से इन चुनौतियों को एक सीमा तक समाप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में शिक्षा में डिजिटल शिक्षा (प्रौद्योगिकी) का महत्व

शिक्षा जुलाई 2020 में, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यह नीति शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर स्तर पर प्रौद्योगिकी का समावेश करती है। एनईपी 2020 में कहा गया है कि शिक्षा प्रणाली के मुख्य चालकों में से "एक शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग, भाषा बाधाओं को दूर करना, शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा योजनाओं को लागू करने और उनका प्रबंधन करना होगा।"

वर्तमान दौर में, कोरोना महामारी की स्थिति से गुजरने के बाद शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेश और अधिक प्रासंगिक हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई पीढ़ी को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद करेगा।

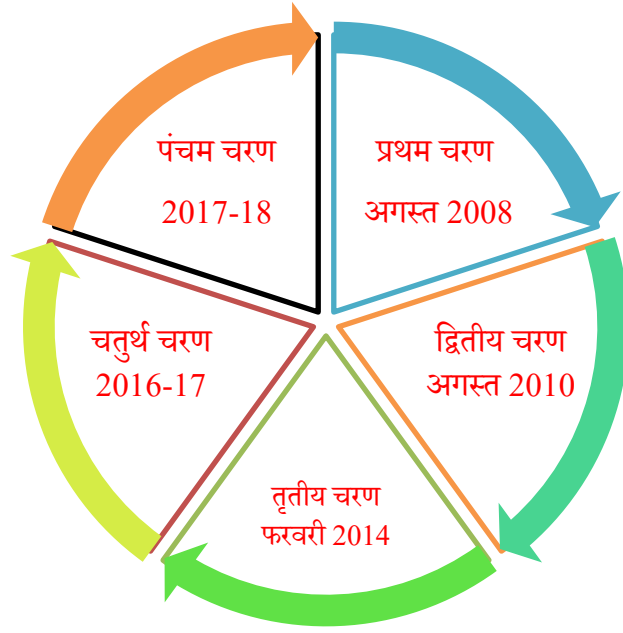
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार डिजिटल सामग्री, बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित ई-शिक्षा इकाई और एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) की स्थापना की जाएगी। एनईटीएफ के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, कंप्यूटिंग डिवाइस और अन्य शैक्षिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करने, छात्र प्रगति को बढ़ावा देने, शिक्षकों के विकास में सहायता करने और प्रशासन और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी स्तरों पर शिक्षा में शामिल किया जाएगा।

आई सी टी लैब (ICT Lab)

आई सी टी लैब एक तकनीकी संसाधन है जो शिक्षा क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। यह लैब विद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में आधुनिक शिक्षा साधनों के उपयोग को सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सामग्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य तकनीकी साधन होते हैं जो विद्यार्थियों को सिखाने में मदद करते हैं। विद्यालय प्रमुख आई सी टी प्रभारी के सहयोग समय-सारणी अनुसार विद्यार्थियों को शिक्षा क्षेत्र में तकनीक के उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें।

सूचना एवं संचार तकनीकी के उपयोग से विद्यालय स्तरीय निष्पादन क्षमता के संवर्धन तथा शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को सुगम, सुरक्षित और सर्व सुलभ बनाने के लिये आईसीटी उपकरणों की व्यवस्था द्वारा वर्तमान पाठ्यक्रम और विधियों को समृद्ध कर विद्यार्थियों को डिजिटल विश्व से आत्मसात् करवाने और प्रभावी रोजगार के लिये आवश्यक कौशलों को प्राप्त करने के योग्य बनाने हेतु राज्य के विद्यालयों में आई.सी.टी. का उपयोग प्रारम्भ किया गया। विद्यालयों में आईसीटी का उपयोग दो दृष्टिकोणों से किया गया है :- आईसीटी "स्वयं एक विषय" के रूप में तथा दूसरा "शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संवर्धन उपकरण" के रूप में।

राजस्थान में आई सी टी योजना :- आई सी टी योजनान्तर्गत विभिन्न चरणों में विद्यालयों में आई सी टी लैब को स्थापित की गई है।



आई सी टी योजना अंतर्गत चरणवार विद्यालय को प्राप्त सामग्री :-



प्रथम चरण :-

- प्रथम चरण के अंतर्गत अगस्त 2008 में राज्य के 2500 विद्यालयों में बूट मॉडल अनुबंध आधार पर प्रत्येक स्कूल में 10 कम्प्यूटर सेट मय आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाये गये और विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु संसाधन प्रदान किये गये है। इस चरण की बूट अवधि 31.12.2013 को समाप्त हो गई है।

द्वितीय चरण :-

- द्वितीय चरण के अंतर्गत अगस्त 2010 में राज्य के 2000 विद्यालयों में बूट मॉडल अनुबंध आधार पर प्रत्येक स्कूल में 10 कम्प्यूटर सेट मय आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाये गये।
- इस चरण की बूट अवधि 31.08.2015 को समाप्त हो चुकी है।

तृतीय चरण:-

- तृतीय चरण के अन्तर्गत फरवरी, 2014 में संस्कृत विद्यालयों को सम्मिलित करते हुये राज्य के 2000 विद्यालयों में बूट मॉडल अनुबंध आधार पर प्रत्येक स्कूल में 10 कम्प्यूटर सेट मय आवश्यक सामग्री और सौलर पेनल आदि उपलब्ध करवाये गये।
- इस चरण के 2000 विद्यालयों में सैटेलाइट प्रसारण के माध्यम से कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित, अंग्रेजी व कम्प्यूटर विषय का लाइव कक्षाएँ भी संचालित की गई।
- इस चरण की बूट अवधि 24 फरवरी 2019 को समाप्त हो चुकी है।

चतुर्थ चरण :-

- चतुर्थ चरण वर्ष 2016-17 में विभाग द्वारा एनआईसीएसआई के माध्यम से राज्य के 525 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर लैब की स्थापना की गई।
- विद्यालयों में 12 कम्प्यूटर, 1 यूपीएस, 13 कम्प्यूटर टैबल, 24 चेयर, 1 प्रिन्टर, उपलब्ध करवाये गये है। वर्ष 2017-18 से 1 टी0वी0, 1 डिश एन्टीना, 1 सेटअप बाक्स उपलब्ध करवाये गये है।

पंचम चरण :-

- पंचम चरण के लिये वर्ष 2017-18 में राज्य के 303 राजकीय माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब स्थापित की गई है।

सत्र 2020-21 हेतु पीएबी में स्वीकृत कम्प्यूटर लैब का विवरण

इस बजट सत्र 2020-21 में आई.सी.टी. कार्यक्रम के विस्तार हेतु आईसीटी एण्ड डिजिटल इनिशिएटिव योजनान्तर्गत 108 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 417 राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब संस्थापना एवं 11 स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों में 22 स्मार्ट क्लासरूम तथा 22 राजकीय महात्मा गाँधी विद्यालयों में 44 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित कर आई.सी.टी. कार्यक्रम का विस्तार किया गया है।

स्मार्ट कक्षा - कक्ष

पहले दुनिया के प्रत्येक विद्यालय के कक्षा में एक ब्लैकबोर्ड या व्हाइट बोर्ड होता था। आज भी बहुत सारे विद्यालय में इनका उपयोग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए किया जा रहा है जिस पर एक शिक्षक के लिए पढ़ाना काफी कठिन होता है क्योंकि काफी समय लिखने और लिखकर समझाने में खत्म हो जाता है या कई बार लिखावट ऐसी होती है कि पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है और अगर चित्र बनाने की जरूरत पड़े तो काफी मुश्किल हो जाता है जिससे विषय वस्तु को समझने या समझाने में दिक्कत होती है। आज के आधुनिक युग में ब्लैकबोर्ड या व्हाइट बोर्ड की जगह डिजिटल कक्षा-कक्ष (स्मार्ट कक्षा कक्ष) में शिक्षा देना आसान हो गया है।

जिस कक्षा-कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है या जिस कक्षा-कक्ष में शिक्षा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ब्लैकबोर्ड या व्हाइटबोर्ड की जगह डिजिटल/स्मार्ट / इंटरएक्टिव बोर्ड, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर) लगे होते हैं, स्मार्ट कक्षा-कक्ष होते हैं। इन डिजिटल कक्षा-कक्ष में स्मार्ट बोर्ड को उपयोग में लाया जाता है। स्मार्ट बोर्ड USB केबल से और प्रोजेक्टर VGA केबल की सहायता से कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, इन सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से जिस कक्षा-कक्ष में पठन-पाठन का कार्य किया जाता है, स्मार्ट कक्षा-कक्ष कहलाता है।

स्मार्ट कक्षा-कक्ष में स्मार्ट बोर्ड पर चाक या मार्कर पेन से ना लिखकर किसी डम्मी पेन या अपनी अंगुली की सहायता से लिखा जाता है। स्मार्ट कक्षा-कक्ष में स्मार्ट बोर्ड पर वीडियो की सहायता से बच्चों को तरह-तरह के चित्र या फिल्म दिखा कर पठन-पाठन का कार्य कराया जाता है जो डिजिटल फॉर्मेट में सरलता से उपलब्ध होते हैं तथा एक बार पढ़ाये गए विषय-वस्तु को बार बार दोहराया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में स्मार्ट टी वी उपलब्ध करवाई गई है परन्तु जिन विद्यालय में स्मार्ट टी वी नहीं है उन विद्यालय के संस्था प्रमुख भामाशाह के सहयोग से प्राप्त करें और शिक्षक को स्मार्ट टी वी का उपयोग, उसका रख रखाव इसके बारे में चर्चा करें।

स्मार्ट कक्षा के उपकरण:- स्मार्ट कक्षा-कक्ष में उपयोग होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस प्रकार होते हैं :-

- **Smart Board** - स्मार्ट बोर्ड एक डिजिटल इंटरएक्टिव बोर्ड होता है, जिसकी सहायता से स्मार्ट क्लास तैयार किया जाता है। इंटरएक्टिव बोर्ड तीन तरीके के होते हैं, जिनका उपयोग कक्षा कक्ष में किया जा सकता है
- **Computer** - स्मार्ट कक्षा-कक्ष में कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रयोग किया जा सकता है जिससे डिजिटल कंटेंट को रन करवा कर सरलता से अध्ययन का कार्य करवाया जा सकता है
- **Projector** - प्रोजेक्टर का प्रयोग कक्षा-कक्ष में स्मार्ट बोर्ड से कंप्यूटर या लैपटॉप के द्वारा प्राप्त इंस्ट्रक्शन को बोर्ड पर प्रोजेक्ट करना होता है, जिसमें किसी भी तरह का प्रोजेक्टर का उपयोग किया जा सकता है जैसे लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर, शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर या अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर।
- **Speaker**- स्पीकर का प्रयोग कक्षा-कक्ष में मुख्यतः डिजिटल कंटेंट और ऑडियो कंटेंट सुनने के लिए किया जाता है। कक्षा-कक्ष साइज के अनुसार स्पीकर का उपयोग किया जाना चाहिए ताकि आवाज साफ सुनाई दे।

स्मार्ट कक्षा-कक्ष के लाभ :-

1. स्मार्ट कक्षा-कक्ष के द्वारा अध्ययन सामग्री को बड़े ही प्रभावी तरीके से व कठिन से कठिन विषय को सरलता से समझने या समझाने में मदद मिलती है।
2. किसी भी अध्ययन सामग्री को बार-बार देखा और देखकर समझा जा सकता है।
3. किसी भी अध्ययन सामग्री को चित्र और वीडियो के माध्यम से समझने और समझाने में आसानी होती है।
4. चित्र और विडिओ के माध्यम से समझाया जा सकता है यह स्थाई रूप से याद भी रहता है
5. अपने किए गये कार्य को सेव कर रख सकते हैं और कभी भी इसे दुबारा देखा जा सकता है

डिजिटल शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार की पहल

पीएम ई-विद्या कार्यक्रम

डिजिटल शिक्षा के महत्व और वर्तमान परिदृश्य में भी स्कूली शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने की इसकी क्षमता को समझते हुए पीएम विद्या कार्यक्रम के तहत डिजिटल/ऑनलाइन शिक्षा के बहु साधन अभिगम (multi & mode access) के लिए एक कार्यक्रम 17 मई, 2020 को शुरू किया गया। एक व्यापक पहल के रूप में, पीएम ई-विद्या डिजिटल/ऑनलाइन / ऑन-

एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एक करने की कल्पना को चरितार्थ करने की कोशिश कर रहा है, जिससे देश भर के लगभग 25 करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। इन पहलों में शामिल हैं-



दीक्षा (DIKSHA) राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के सभी वर्गों / कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाली पाठ्यपुस्तकें, मूक्स (MOOCS) पाठ्यक्रम तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों के लिए स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई कंटेंट प्रदान करने के लिए देश की डिजिटल संस्था (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म)

स्वयं प्रभा (SWAYAM PRABHA) 1 से 12 तक प्रति कक्षा एक टीवी चैनल (एक कक्षा, एक चैनल)

स्वयं (SWAYAM) ओपन स्कूल या एन आई ओ एस (NIOS) के लिए मूक्स (MOOCS) प्रारूप में ऑनलाइन पाठ्यक्रम
ऑन एयर रेडियो सामुदायिक रेडियो और सी बी एस ई पॉडकास्ट शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग, दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए विशेष ई सामग्री डिजिटल रूप से सुगम्य सूचना प्रणाली (DAISY) पर विकसित और एन आई ओ एस वेबसाइट/यू-ट्यूब पर सांकेतिक भाषा में उपलब्ध सामग्री।

ऑनलाइन कोचिंग आई आई टी, जे ई ई/नीट (NEET) की तैयारी के लिए आई टी पी ए एल (ITPAL)

डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किये गये नवाचार

राज. ई-ज्ञान :- इस पोर्टल का निर्माण DO&IT एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा वर्ष 2015 में किया गया। राज-ई ज्ञान पोर्टल के माध्यम से विद्यालय स्तरीय विषयवस्तु ई-कंटेंट, पावर पाइंट एनिमेशन विडियो आडियो तथा पुस्तक आदि विभिन्न डिजिटल प्रारूपों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, शिक्षाविदों व अभिभावकों हेतु हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध करवाई जा रही है।

ई-कक्षा (E-KAKSHA) :- ई-कक्षा परियोजना को स्कूली शिक्षा की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए और छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार किसी भी समय लाभान्वित करने के लिए माहामारी युग के दौरान राजस्थान के सभी विद्यार्थियों को समान मंच साझा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस परियोजना के दौरान 28 जुलाई 2020 को शिक्षा विभाग, केयर्न फाउंडेशन और मिशन ज्ञान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, तथा कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए अनुभवी स्कूल शिक्षकों द्वारा ई-कॉन्टेंट तैयार किया और सभी विषयों के लिए पहली 'डिजिटल लाइब्रेरी' को तैयार किया। कक्षा 6वीं से 12वीं तक: यूट्यूब चैनल में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के हिंदी माध्यम के सभी विषयों के वीडियो शामिल हैं जिन्हें किसी भी समय संशोधित और अध्ययन किया जा सकता है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे :- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नीति के तहत, ई-कक्षा परियोजना विशेष छात्रों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सांकेतिक भाषाओं में वीडियो बना रही है।

एनसीईआरटी कक्षा 1 से 10वीं तक :- कक्षा 1 से 10वीं (अंग्रेजी माध्यम) के लिए एनसीईआरटी अंग्रेजी पाठ्यक्रम और अध्याय ई-कक्षा अंग्रेजी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए हैं। सभी सरकारी स्कूलों में जहां विषय शिक्षकों की अनुपलब्धता है, वहां सभी वीडियो आईसीटी लैब या स्मार्ट बोर्ड में प्रदर्शित करने के लिए हार्ड डिस्क उपलब्ध करवाई गई है यह हार्ड डिस्क शिक्षकों को संस्था प्रधान द्वारा दे दी जाती है जिसका उपयोग वे शिक्षण को प्रभावी रूप से करने के लिए कर सकते हैं इसके अतिरिक्त छात्रों के लिए बिना लॉग इन के ई-कक्षा ऐप भी उपलब्ध है -

<https://missiongyan.com/ekaksha/>

हवामहल कोरोना समय में बच्चों का झरोखा :- यह साप्ताहिक ई-पत्रिका RSCERT उदयपुर और सहयोगी संस्थाओं की साझेदारी में बच्चों की पठन पाठन में रुचि एवं चिंतन अभिवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अप्रैल 2020 से प्रारम्भ की गयी जो वर्तमान में भी जारी है।

SMILE प्लेटफॉर्म के विभिन्न व्हाट्सअप समूहों से प्रत्येक शनिवार बच्चों एवं शिक्षकों के लिए इन्टरैक्टिव शैक्षिक सामग्री भेजी जाती है। टाटा ट्रस्ट के पराग इनीशियेटिव और सीएमएफ के तकनीकी सहयोग से प्रथम बुक्स, अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन, रूम टु रीड, सेव द चिल्ड्रन, पिरामल फाउंडेशन एवं यूनीसेफ द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है।

राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम :- 11 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के स्कूली छात्रों को कोरोना काल में हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने के लिये रेमेडिएशन कार्यक्रम 'राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। गौरतलब है कि कोविड के कारण हुई नौनिहालों की शैक्षिक क्षति की भरपाई के लिये वर्ष 2022-23 के बजट में 75 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान से 'ब्रिज कार्यक्रम' की घोषणा की गई थी। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम' कार्यक्रम के तहत ब्रिज कोर्स में रटने की बजाय सीखने पर बल दिया गया। ब्रिज कोर्स में कक्षा 1 से 8 के लिये प्रथम तीन माह में 4 कालांश तथा शेष संपूर्ण सत्र में 2 कालांश निर्धारित किए गए। योजनांतर्गत 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिये दक्षता आधारित कार्यपुस्तिकाएँ तैयार की गईं तथा वर्ष में 3 बार दक्षता का आकलन किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत नियमित शिक्षक अभिभावक बैठकों में होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिए जाते हैं।

इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के कार्यक्रम संचालित होंगे तथा कक्षा 3 से 8 तक के सभी शिक्षकों हेतु टीचिंगएड ऐप की सुविधा भी उपलब्ध कराई गयी। शिक्षा के बढ़ते कदम अभियान के तहत 1.35 करोड़ विद्यार्थियों ने दी थी परीक्षा, World Book of Records में रिकॉर्ड दर्ज हुआ। वर्तमान वर्ष में भी यह कार्यक्रम सफलता पूर्वक चल रहा है।

असेसमेंट सेल:- राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (आरएससीईआरटी), उदयपुर एक स्वायत्त राज्य संस्थान और राजस्थान के लिए शैक्षणिक नोडल केंद्र है। मूल्यांकन के उद्देश्य को मूल्यांकन और निगरानी से बदलकर शिक्षकों

द्वारा कक्षा के निर्देशों में सुधार के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण में बदलाव आरएससीईआरटी पर सही दिशा में पहल करने और मूल्यांकन पर शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करने का दायित्व डालता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 और विश्व बैंक द्वारा राज्यों के लिए शिक्षक-शिक्षण और परिणाम को मजबूत करने के कार्यक्रम (स्टार्स) ने सिफारिश की है कि राज्य एजेंसियां 2022-23 तक मूल्यांकन में परिवर्तन के लिए संस्थान स्थापित करें। राज्य मूल्यांकन सेल/केंद्र की स्थापना गुणवत्ता मानकीकृत मूल्यांकन की पेशकश में गेम चेंजर के रूप में कार्य कर सकती है और गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमित डेटा प्रदान करने में भी सहायता कर सकती है।

एनएस और नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस) जैसी कई मूल्यांकन-संबंधित गतिविधियां प्रभाग के नेतृत्व में हैं। इसलिए, मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाले स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों को समर्पित रूप से निष्पादित करने के लिए आरएससीईआरटी, उदयपुर में एक मूल्यांकन कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था। मूल्यांकन सेल बेहतर शैक्षिक परिणामों के लिए शिक्षण-सीखने की प्रथाओं में उन्हें एकीकृत करने के लिए व्यापक शोध के माध्यम से मूल्यांकन की वर्तमान प्रथाओं को फिर से डिजाइन और पुनर्गठित करेगा। यह सेल उदयपुर में आरएससीईआरटी मुख्यालय से कार्य करता है, जो नीति निर्माण के लिए अपनी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त डेटा की गोपनीयता बनाए रखता है।

मूल्यांकन सेल में अत्यधिक प्रेरित और कुशल शिक्षक शामिल हैं जो राज्य के भीतर प्रणालीगत मूल्यांकन सुधारों का नेतृत्व करने वाले मूल्यांकन क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं। यह सेल कई मूल्यांकन हस्तक्षेपों को डिजाइन करने और निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है। मूल्यांकन सेल राज्य के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन नीतियों को प्रासंगिक बनाने के लिए कार्यक्रम विकसित करेगा, जिससे राजस्थान देश में सर्वोत्तम इन-हाउस मूल्यांकन प्रणालियों के साथ एक मॉडल राज्य बन जाएगा, जो उच्चतम गुणवत्ता मानक शिक्षा तक पहुंचने के लिए संस्थानों और हितधारकों को मजबूत करेगा।

मिशन स्टार्ट:- पूर्व मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के तत्वधान में 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विभाग नवाचार फ्लैगशिप कार्यक्रम मिशन स्टार्ट 2023-24 का शुभारम्भ किया गया है।

यह कार्यक्रम राज्य के दूरदराज के इलाकों में अध्ययनरत उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जहां शिक्षा की पहुंच पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है अर्थात् इन विद्यालयों में शिक्षको के पद रिक्त हैं अथवा अन्य किसी कारणवश विषयाध्यापकों की उपलब्धता में कमी है। मिशन स्टार्ट के माध्यम से ऐसे विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को विभाग द्वारा निर्मित डिजिटल सामग्री से अध्ययन करवाया जाकर यह सुनिश्चित किया जाना है कि शिक्षको की कमी अनुपस्थिति का प्रतिकूल प्रभाव विद्यार्थी के अध्ययन निरंतर पर ना हो। इन सब में संस्था प्रधान की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शुक्रवार को वह आने वाले सप्ताह की समय सारणी बनवाता है और सूचना बोर्ड पर लगा दिया जाता है।

स्कूल आफ्टर स्कूल प्रोग्राम :- राजस्थान के 10वीं एवं 12वीं बोर्ड में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग की एक अनूठी पहल, जिसमें अब स्कूल टाइम के बाद भी विद्यार्थी "School After School" कार्यक्रम के तहत घर पर Videos के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन कर सकेंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों को अतिरिक्त शैक्षिक अवसर उपलब्ध प्रदान करना उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना।

चिंतन प्रश्न :-

1. क्या आप बिना ICT लैब और स्मार्ट टीवी के दीक्षा प्लेटफॉर्म से कंटेंट द्वारा अपने विद्यार्थियों को शिक्षण में मदद कर सकते हैं ?
2. आप पी एम ई विद्या चैनल के लिए ई कंटेंट किस प्रकार तैयार कर सकते हो ?
3. यदि कोविड के समय विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए डिजिटल तकनीकी का उपयोग नहीं किया होता तो उनके शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता ?

समेकन:-

ऑनलाईन प्रक्रिया में आई. सी. टी. लैब और स्मार्ट क्लास रूम संचालन में विद्यालय प्रमुख की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। राजस्थान जैसे राज्य में जहाँ संसाधनों (ICT की बुनियादी सुविधाएँ, बिजली, बजट, कुशल जनशक्ति) की उपलब्धता के संदर्भ में विविधतापूर्ण विशिष्ट विविधता और बाधाएँ हैं। यहाँ शिक्षा के डिजिटल तरीकों के माध्यम से कार्य करना एक विशालकाय एवं चुनौतियों भरा कार्य है परन्तु एक कुशल विद्यालय प्रधान अपनी कुशलता से इस चुनौती को आसानी से समाप्त कर सकता है। उन्हें डिजिटल शिक्षा के सम्बन्ध में सभी सूचनाओं से हमेशा अपडेट रहना चाहिए। उन्हें डिजिटल फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे वह आई सी टी लैब और स्मार्ट रूम का उपयोग कर सके। उन्हें दीक्षा, निष्ठा, मिशन स्टार्ट, स्माइल, हवा महल, रेडियो प्रसारण कार्यक्रम, पी एम ई विद्या आदि सभी का ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए वह अपने साथियों अपने विद्यालय स्टाफ की भी सहायता ले सकते हैं। इस तरह सहयोग की भावना से वह शिक्षक के अभाव में भी हर दिन अपने विद्यार्थियों को प्रभावी और रुचिपूर्ण शिक्षण करवा सकते हैं।

सन्दर्भ सूची :-

- राष्ट्रीय शिक्षा निति 2020
- प्रज्ञाता – विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार
- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर के पत्र क्रमांक :रामाशिप/जय/आईसीटी/Gen./ 2020/ 16006 दिनांक 19/10/2000



लेखक :-

शमीम

प्रधानाचार्य

श्री बंशीधर पुरोहित राजकीय माध्यमिक विद्यालय विद्याशाला, जोधपुर